साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 01-07 जुलाई 2024 वर्ष-10, अंक-11

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि को लेकर केंद्र सरकार के 5 साल के रोडमैप को रखा सामने

ग्रामीण अर्थव्यवस्था, एमएसपी और प्राकृतिक खेती पर फोकस

भोपाल। जागत गांव हमार

18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अभिभाषण हुआ। राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। उन्होंने महिलाओं, युवाओं, किसानों, गरीबों के बारे में बात की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में देश के अगले 5 वर्षों के लिए सरकार के कामकाज की रूपरेखा सामने रखी और विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर दे रही है। किसानों की आय और उनकी उपज बढ़ाने के साथ ही भंडारण को लेकर संजीदगी से काम कर रही है। आने वाला समय हरित युग का है, हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं। सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। हम हरित उद्योगों पर निवेश बढ़ा रहे हैं, जिससे ग्रीन जॉब भी बढ़े हैं। रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफार्म के संकल्प ने आज भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना दिया है।

एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी

राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के तहत देश के किसानों को 3 लाख 20 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की है। मेरी सरकार के नए कार्यकाल की शुरुआत से अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों को हस्तांतरित की जा चुकी है। सरकार ने खरीफ फसलों के लिए एमएसपी में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी की है।

कृषि उद्योगों को बढ़ावा | राष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था की हर वैल्यू पर बहुत जोर दिया है। गांव में कृषि आधारित उद्योगों डेयरी और फिशरीज आधारित उद्योगों का विस्तार किया जा रहा है। इसमें भी सहकारिता को प्राथमिकता दी गई है। सरकार किसानों उत्पाद संघ, एफपीओ और कृषि जैसे सरकारी संगठनों का बड़ा नेटवर्क बना रही है।छोटे किसानों की समस्या भंडारण को लेकर होती है, इसलिए हमारी सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू की है।

प्राकृतिक खेती-प्रोडक्ट के लिए सप्लाई चेन

आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। आजकल दुनिया में जैविक उत्पादों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारतीय किसानों के पास इस मांग को पूरा करने की पूरी क्षमता है इसलिए सरकार प्राकृतिक खेती और इससे जुड़े उत्पादों की सप्लाई चेन को सशक्त कर रही है।

दलहन-तिलहन में होंगे आत्मनिर्भर

आज का भारत अपनी वर्तमान जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपनी कृषि व्यवस्था में बदलाव कर रहा है। हम ज्यादा से आत्मनिर्भर हों और ज्यादा से ज्यादा निर्यात से किसानों की आमदनी बढ़े, यह सोचकर नीतियां बनाई गई हैं। भारत दलहन और तिलहन में दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने के लिए देश के किसानों को हर संभव मदद दी जा रही है। बाजार में किस तरह के फूड प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है, इसके आधार पर नई रणनीति बनाई जा रही है।

सीएम मोहन के सुझाव पर केंद्रीय मंत्री शिवराज ने लगाई मुहर

मप्र में कोदो-कुटकी की एमएसपी पर होगी खरीदी

» रागी के समर्थन मूल्य 4290 रुपए पर ही होगी कोदो-कुटकी की खरीद

» मूंग की खरीद की अनुमति अभी भी भारत सरकार ने मप्र को दी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के सुझाव पर केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मप्र में पैदा होने वाले श्री अन्न कोदो कुटकी को भी रागी की तरह समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने का फैसला किया है। शिवराज ने कहा कि अभी तक एमएसपी पर कोदो-कुटकी की खरीदी नहीं होती थी, अब हमने 4 हजार 290 रुपए, जो रागी का समर्थन मूल्य है, उसी पर कोदो-कुटकी की खरीदी करने का फैसला किया है, ताकि श्रीअन्न को हम बढ़ावा दे सकें और आदिवासी भाई-बहनों को उचित दाम मिल सके। शिवराज ने कहा कि मप्र के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के कई विषयों को लेकर आए, उनसे भेंट हुई। मैंने सारे अधिकारियों को बुलाकर तत्काल चर्चा की, जैसा उन्होंने बताया प्रधानमंत्री श्री अन्न को प्रोत्साहित करने का आह्वान है, मोटे अनाज के फायदे हम सब जानते हैं। मध्य प्रदेश में कोदो-कुटकी ये मोटे अनाज के रूप में विशेषकर आदिवासी क्षेत्र में होता है।

सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज मैंने कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक की और कुछ निर्णय भी लिए। हमारे राज्य की फसल कोदो कुटकी एमएसपी में छूट गई थी, रागी उसके समकक्ष फसल है ऐसे में कोदो कुटकी की एमएसपी को उसके बराबरी में लाने का मैंने सुझाव दिया। इसे मानने के लिए मैं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि दलहन और पाम ऑइल को लेकर भी उन्होंने सुझाव दिए हैं।

सिंचाई में अग्रणी राज्य

मुख्यमंत्री मोहन ने बताया कि प्रदेश में नहर से सिंचाई व्यवस्था के स्थान पर प्रेशराइज्ड पाइप से खेतों में पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। प्रधानमंत्री के मोर ऑप, पर ड्रॉप के संकल्प पर काम करते हुए मप्र इस प्रेशराइज्ड पाइप से सिंचाई व्यवस्था में अग्रणी राज्य है। प्रेशराइज्ड पाइप के आउटलेट्स पर ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था लगाने के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मिलने से किसानों को और अधिक फायदा होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने केंद्रीय कृषि मंत्री से ड्रिप इरीगेशन और स्प्रिंकलर व्यवस्था के अंतर्गत प्रदेश के लक्षित क्षेत्रफल को बढ़ाए जाने का अनुरोध किया।

जनमन में भारिया जनजाति को जोड़ेंगे

कृषि मंत्री शिवराज ने कहा कि जनमन में छिंदवाड़ा जिला छूट गया था, पीएम जनमन योजना में वहां भारिया नाम की एक जनजाति रहती है तो उसके बारे में भी चर्चा हुई। जनमन योजना में उन्हें भी जोड़ने का काम करेंगे। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकसित भारत के लिए मध्य प्रदेश विकसित बने तो कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय मध्य प्रदेश को पूरा सहयोग करेगा।

मूंग खरीदी की अनुमति | शिवराज ने कहा कि अभी भारत सरकार ने मध्य प्रदेश को मूंगी की खरीदी की भी मंजूरी दी है। गर्मी में मूंग काफी होता है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि, मूंग भारी मात्रा में उत्पादित हुआ है तो उस विषय को भी हम गंभीरता से देख रहे हैं। शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश ने एक काम बहुत अच्छा किया है, मोहन उस काम को बहुत तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।

कंषाना ने कृषि मंत्री का माना आभार

इधर, मप्र के कृषि विकास मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान का किसान हितैषी निर्णयों के लिए आभार व्यक्त किया है। कंसाना ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार किसानों के हित में सतत निर्णय ले रही है। मंगलवार को मंदिर परिषद की बैठक में विकासखंड स्तर पर नवीन मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमीयो या संस्थाओं को उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी है। सरकार के द्वारा लिए गए इस ऐतिहासिक फैसले से हजारों नौजवानों को रोजगार मिलेगा साथ ही मिट्टी परीक्षण प्रयोग-शालाओं का बेहतर उपयोग किया जाकर किसानों को उत्पादन बढ़ाने में आवश्यक सुझाव देकर मदद की जा सकेगी।

सीएम डॉ. मोहन की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद के अहम निर्णय

अब विकासखंड स्तर पर सरकार स्थापित करेगी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंत्रालय में हुई। मंत्रि-परिषद द्वारा विकासखंड स्तर पर कृषकों को मिट्टी परीक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के द्वारा नवीन मिटटी परीक्षण प्रयोगशालाओं के भवन एवं यथा उपलब्ध प्रयोगशाला उपकरणों को युवा उद्यमियों/संस्थाओं को उपलब्ध कराए जाने की मंजूरी दी गई है। इससे युवा उद्यमियों संस्थाओं के माध्यम से किसानों के मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर मृदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे। वहीं मंत्रि-परिषद ने राजपत्र दिनांक 10 दिसंबर 2021 में प्रकाशित संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सीएसआर/सीईआर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन का निर्णय लिया।

» उपकरणों को युवा उद्यमियों व संस्थाओं को उपलब्ध कराने की मंजूरी

» सीएसआर निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण की नीति में संशोधन

समारोह के दौरान प्रमुख सचिव पशुपालन गुलशन बामरा रहे मौजूद

केंद्रीय मंत्री बोले-गणना के आंकड़े सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे में योगदान देंगे

अगली पशुगणना की चुनौतियों से निपटने केंद्र सरकार ने लॉन्च किया मोबाइल एप

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में 21वीं पशुधन गणना की तैयारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीति बनाने और सशक्त करने के लिए कार्यशाला का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल और जॉर्ज कुरियन भी मौजूद थे। कार्यशाला में केंद्रीय मंत्री ने 21वीं पशुधन डेटा संग्रह के लिए विकसित मोबाइल एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया। केंद्रीय मंत्री ने भारत की अर्थव्यवस्था और खाद्य सुरक्षा के लिए पशुधन क्षेत्र का महत्व बताया। उन्होंने पशुधन गणना की सावधानीपूर्वक योजना बनाने और उसे लागू करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि एकत्र किया गया डाटा, भविष्य की पहलों को आकार देने और क्षेत्र में चुनौतियों का समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कार्यशाला का उद्देश्य सितंबर-दिसंबर 2024 के दौरान निर्धारित आगामी पशुधन गणना के लिए एक समन्वित और कुशल दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है। गणना के आंकड़े सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे में योगदान देंगे, जिससे व्यापक राष्ट्रीय और वैश्विक स्थिरता लक्ष्यों के साथ तालमेल किया जा सकेगा।

तकनीकों का उठाएं लाभ

पशुपालन एवं डेयरी विभाग की सचिव अलका उपाध्याय ने कहा कि यह विभाग सटीक और कुशल डेटा संग्रह के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने 21वीं पशुधन गणना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए सभी हितधारकों की सामूहिक जिम्मेदारी पर बल दिया। साथ ही कहा कि यह पशुपालन क्षेत्र की भविष्य की नीतियों और कार्यक्रमों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने गणना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए नवीनतम तकनीकों का लाभ उठाने का आग्रह किया।

प्रजातियों के नस्ल विवरण पर प्रस्तुति

कार्यशाला में 21 वीं पशुधन गणना के लिए कार्यप्रणाली और दिशा-निर्देशों पर विस्तृत सत्र, मोबाइल एप्लिकेशन और डैशबोर्ड सॉफ्टवेयर पर प्रशिक्षण और प्रश्नों और चिंताओं के समाधान के लिए एक खुली चर्चा शामिल थी। मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने 21वीं पशुधन गणना की तैयारी के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रणनीति बनाने और सशक्त करने के लिए एक व्यापक कार्यशाला आयोजित की। कार्यशाला में कई सत्र आयोजित किए गए। इस दौरान पशुपालन सांख्यिकी प्रभाग ने 21वीं पशुधन गणना का संक्षिप्त विवरण दिया और बाद में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो द्वारा गणना में शामिल की जाने वाली प्रजातियों के नस्ल विवरण पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई।

सटीक नस्ल पहचान के महत्व पर फोकस

सटीक नस्ल पहचान के महत्व पर जोर दिया गया। सटीक नस्ल पहचान, विभिन्न पशुधन क्षेत्र कार्यक्रमों में उपयोग किए जाने वाले सटीक आंकड़े तैयार करने और सतत विकास लक्ष्यों के राष्ट्रीय संकेतक ढांचे के लिए महत्वपूर्ण है। इस वर्कशॉप में गुलशन बामरा प्रमुख सचिव पशु पालन विभाग मध्यप्रदेश शासन के साथ संचालनालय पशु पालन विभाग डॉ. उमा कुमरे (परते) प्रभारी पशु सांख्यिकी प्रभाग के साथ संभाग स्तरीय अधिकारी डॉ. अभिषेक शुक्ला जबलपुर, डॉ. संतोष शुक्ला इंदौर, डॉ. स्मृति मिश्रा उज्जैन, डॉ. आरजी शर्मा ग्वालियर, डॉ. अजय यादव सागर, डॉ. शिरीन दुबे रीवा. डॉ. तन्मय गर्ग डॉ. रश्मि चंद्राकर भोपाल उपस्थित रहे। आगामी पशु गणना आगामी सितंबर से प्रस्तावित है।

किसानों को खेत से प्रयोगशाला तक जोड़ने का बन रहा रोडमैप

कृषि मंत्री शिवराज बोले- विकसित भारत के लिए विकसित खेती जरूरी

खेत से लेकर प्रयोगशालाओं तक अब किसानों को जोड़ेगी सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

किसान कल्याण के साथ ही उन्नत तरीके से खेती किए जाने को लेकर मोदी 3.0 सरकार का खास फोकस दिख रहा है। 100 दिन के विकास एजेंडे के साथ जमीन पर उतरे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान झारखंड के रांची पहुंचे। रांची में उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए विकसित खेती जरूरी है। खेत से लेकर प्रयोगशालाओं तक किसानों को जोड़ने के लिए रोडमैप तैयार हो रहा है। विज्ञान से किसान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने झारखंड में परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों और सब्जी की खेती के साथ ही लाख की खेती के विकास पर जोर दिया। झारखंड में कृषि क्षेत्र के लिए अपार संभावनाएं हैं। शिवराज ने कहा ने कहा कि झारखंड में आकर मैंने जमीनी दौरा किया है। प्रधानमंत्री मोदी का जो संकल्प है- विकसित भारत के लिए विकसित खेती जरूरी है। इसके लिए रोडमैप तैयार किया जा रहा है। खेत से लेकर प्रयोगशालाओं तक किसानों को जोड़ा जाएगा। विज्ञान से किसान को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। झारखंड में कृषि को लेकर अपार संभावनाएं हैं। यहां परंपरागत खेती के अलावा फूलों की खेती, फलों की खेती, सब्जी की खेती है। लाख की खेती की भी अपार संभावनाएं हैं।

किसानों की आय बढ़ाने पर किया जाए काम

शिवराज ने उपस्थित वैज्ञानिकों से आह्वान करते हुए कहा कि पारंपरिक कृषि के साथ-साथ अन्य बेहतर कृषि प्रणालियों के विकास से ही उत्पादन और किसानों की आय को बढ़ाया जा सकता है। किसानों की आय कैसे बढ़ाई जाए और किसानों को तकनीकी तौर पर सक्षम बनाने के लिए क्या शोध किए जाए इस पर जोर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि किसानों की आय बढ़ेगी तब ही देश मजबूत होगा। शिवराज सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि दश की तीन करोड़ लखपति दीदियों में से कम से कम एक लाख लखपति दीदी लाह उत्पादन और इससे संबंधित व्यवसायों से जुड़ें। इससे सभी को लाभ होगा। इसके लिए पहल करने की जरूरत है।

लाह को पूरे देश में मिले कृषि का दर्जा

राष्ट्रीय कृषि उच्चतर प्रसंस्करण संस्थान के निदेशक डॉ.अभिजीत कर ने संस्थान की गतिविधियों,कार्यक्रमों, शोध कार्यक्रम, शिक्षा कार्यक्रम आदि के बारे में संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने कृषि मंत्री को बताया कि झारखंड और छत्तीसगढ़ में लाह की फसल को कृषि का दर्जा दिया गया है। इसी तरह यदि अन्य राज्यों में लाख को कृषि का दर्जा दिया जाए तो किसानों की आय बढ़ेगी और वह काफी सशक्त होंगे। अन्य राज्यों में लाह को वन उपज के रूप में माना गया है, जिससे सरकारी योजनाओं का लाभ इसकी खेती करने वाले किसानों को नहीं मिल पाता है।

मंत्रालय हर संभव मदद के लिए तैयार

कृषि मंत्री रांची के नामकुम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद पूर्वी प्रक्षेत्र के परिसर में भी गए, जहां पर उन्होंने चंदन का एक पेड़ लगाया। इसके बाद उन्होंने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तीनों संस्थानों के निदेशकों के साथ बैठक की जिन्होंने अपने-अपने संस्थान में किए जा रहे कार्यों की कृषि मंत्री का जानकारी दी। तीनों संस्थानों के निदेशकों से जानकारी प्राप्त करने के बाद केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें कृषि मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है। कृषि मंत्री बनने के बाद वो पहली बार अपने कार्य की शुरुआत रांची से कर रहे हैं। तीनों संस्थानों में शोध और नए आविष्कार के लिए जिन भी चीजों की आवश्यकता होंगी, मंत्रालय की तरफ से वो सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।

महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएंगे

नमो ड्रोन दीदी को ट्रेनिंग के साथ मिलेंगे 15 हजार

भोपाल। अब देश की महिलाओं के हाथों में बेलन-चिमटा नहीं, बल्कि ड्रोन कैमरा का रिमोट नजर आएगा। दरअसल, महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी स्कीम लाई है। इस स्कीम के तहत महिलाओं को ड्रोन दीदी के रूप में चयन करके उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया जा रहा है। ड्रोन के इस्तेमाल में महिलाओं को आगे लाने और ग्रामीण महिलाओं को इसके जरिए रोजगार देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत कई ग्रामीण महिलाएं ड्रोन दीदी बन कर बेहतर कमाई कर रही हैं और अपनी आजीविका चला रही हैं। इस योजना के तहत चयन होने पर महिलाओं को 15 दिन तक ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। यहां तक कि ड्रोन दीदी के रूप में जो महिला काम करेगी उसे 15000 रुपये तक की सैलरी भी दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को आधार कार्ड, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज के फोटो और स्वयं सहायता ग्रुप का पहचान पत्र होना जरूरी है।

नमो ड्रोन दीदी योजना

सरकार की इस योजना से कृषि क्षेत्र में भी उत्पादकता बढ़ाने की मंशा है। नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन उड़ाने, डेटा विश्लेषण और ड्रोन के रखरखाव के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल करके अलग-अलग कृषि कार्यों में किसानों की मदद करेंगी। ड्रोन के जरिए वे फसलों की निगरानी, कीटनाशक और उर्वरक का छिड़काव करेंगी। यहां तक कि बीज की बुवाई की भी ट्रेनिंग दी गई है।

स्कीम की खास बातें

कृषि क्षेत्र में महिलाओं का सशक्तिकरण किया जाता है। महिलाओं को ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ड्रोन उड़ाने के बारे में अन्य तकनीकी जानकारी भी दी जाती है। महिलाओं को 15 दिवसीय प्रशिक्षण के साथ 15 हजार रुपये दिए जाते हैं। स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं पात्र हैं।

कैसे होता है ड्रोन दीदी का चयन

केंद्र सरकार के द्वारा नवंबर 2023 में नमो ड्रोन दीदी योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना के तहत देश में 15000 से अधिक महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को स्वयं सहायता समूह का सदस्य होना जरूरी है। वहीं, इस योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं की उम्र 18 से 37 साल के बीच होनी चाहिए।

इस साल 270 लाख टन भी नहीं पहुंच पाई गेहूं की सरकारी खरीद

मप्र में 80 लाख टन की जगह सिर्फ 48.39 टन गेहूं की खरीदी

-देश में 37,05,048 रजिस्ट्रेशन, सिर्फ 21,03,237 किसानों ने ही बेचा

भोपाल। जागत गांव हमार

गेहूं की सरकारी खरीद इस साल 270 लाख टन तक भी पहुंचने की उम्मीद नहीं है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के मुताबिक 26 जून तक सिर्फ 265.53 लाख टन गेहूं ही बफर स्टॉक (सेंट्रल पूल) के लिए खरीदा जा सका है। जबकि सरकार ने 372.9 लाख टन का टारगेट रखा था। 17 से 26 जून तक यानी पिछले 10 दिन में सिर्फ 14540 टन गेहूं ही खरीदा जा सका है। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि खरीद प्रक्रिया खत्म होते-होते आंकड़ा कहां आकर रुक गया। आधिकारिक तौर पर गेहूं खरीद प्रक्रिया बंद हो गई है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में 30 जून को खरीद बंद हो गई। बाकी सूबों में पहले ही खरीद बंद कर दी गई थी। विशेषज्ञों का अनुमान है कि इस साल 266 लाख टन पर खरीद खत्म हो गई है। ऐसा हुआ तो सरकार अपने लक्ष्य से लगभग 107 लाख टन पीछे रह जाएगी। इससे बाजार में दाम बढ़ने का दबाव पड़ सकता है।

बाजार में तीन हजार रुपए क्विंटल

देश में गेहूं की भले ही बंपर पैदावार हुई है लेकिन कम और अधिक सरकारी गेहूं स्टॉक का दाम बढ़ने और घटने पर असर पड़ता है। सरकार के पास कम स्टॉक होगा तो वो कीमतों को काबू में करने के लिए बाजार में ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत सस्ता गेहूं नहीं दे पाएगी। जिससे बाजार में तेजी का रुख कायम रह सकता है। अभी भी बाजार में गेहूं के दाम 2500 से 3000 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहे हैं।

अब तक इतना हुआ भुगतान

देश के 37,05,048 किसानों ने सरकारी एजेंसियों को गेहूं बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन सिर्फ 21,03,237 किसानों ने ही बेचा। बाकी किसानों ने या तो अच्छे दाम की उम्मीद में गेहूं को अपने पास रोक लिया है या फिर सरकारी भाव यानी 2275 रुपए प्रति क्विंटल की एमएसपी से अधिक कीमत पर व्यापारियों को बेच दिया है। बहरहाल, अब तक सरकार 20,21,266 किसानों को 58,619 रुपए का एमएसपी के तौर पर भुगतान कर चुकी है।

खरीदी लक्ष्य से भटका राजस्थान

इस साल 11 राज्यों में खरीद प्रक्रिया चल रही थी, जिनमें से तीन राज्यों गुजरात, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में एक भी दाने की सरकारी खरीद नहीं हुई। जिन चार राज्यों में सबसे अधिक खरीद हुई उनमें पंजाब सबसे ऊपर है। यहां 130 लाख टन के टारगेट के विपरीत 124.54 लाख टन गेहूं की खरीद हुई है। इस मामले में दूसरे नंबर पर हरियाणा है जहां पर 80 लाख टन का टारगेट था और 71.15 लाख टन की खरीद हुई है। मध्य प्रदेश में 80 लाख टन की जगह 48.39 टन की खरीद हुई है। राजस्थान में 20 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया था और अब तक 12.02 लाख टन का आंकड़ा हासिल हो सका है।

-प्रमुख सचिव विवेक पोरवाल ने दिए निर्देश

प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ से निपटने की व्यवस्था रखें

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में वर्षा ऋतु के आगमन पूर्व अतिवृष्टि एवं बाढ़ की स्थिति में जल जनित रोगों उल्टी, दस्त, पेचिश, हैजा, पीलिया, टाईफाइड आदि की संभावना को दृष्टिगत संभावित क्षेत्रों में समुचित चिकित्सकीय सेवा प्रदाय के लिए प्रदेश के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय के अधिष्ठाता, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक और कलेक्टर को आवश्यक तैयारियाँ सुनिश्चित करने के लिए है। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा श्री विवेक कुमार पोरवाल ने निर्देश जारी किए हैं।

पोरवाल ने निर्देश दिये हैं कि जिले के बाढ़ संभावित क्षेत्रों के समस्या मूलक ग्रामों तथा दुर्गम क्षेत्रों को चिन्हित किया जाये तथा बाढ संभावित क्षेत्रों की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम की स्थापना स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय कर स्थापित की जाए। आपदा प्रबंधन के लिए जिले में नोडल अधिकारी मनोनीत किया जाये। अधीनस्थ मैदानी अमलों आशा, एएनएम, एम.पी.डब्लू. सी.एच.ओ., एल.एच.व्ही. तथा पुरूष सुपरवाईजर का मूलभूत चिकित्सकीय उपचार तथा रोगियों के वर्गीकरण विषयों पर उन्मुखीकरण और प्रशिक्षण सुनिश्चित किया जाए।

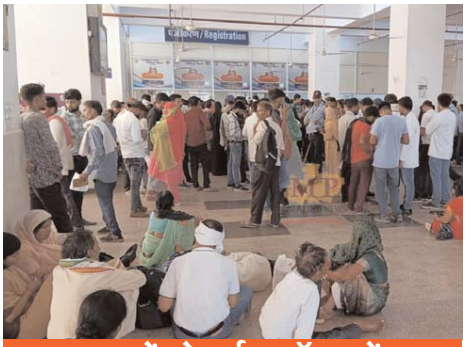

दवाओं को पर्याप्त स्टॉक रखें

चिकित्सा सेवाओं और भू-तल/तहखानों में बने मेडिकल स्टोर को आपात स्थिति में क्षति से बचाव के लिये स्थानीय परिस्थिति अनुसार कार्ययोजना बनाई जाए। अतिवृष्टि से संभावित जल जनित/वेक्टर जनित बीमारियों के उपचार के लिए आशा कार्यकर्ता, एएनएम तथा सीएचओ के पास समस्त आवश्यक औषधियों व सामग्री ओआरएस, क्लोरीन टेबलेट, पैरासीटामॉल, मेट्रोनिडजोल, मेटोक्लोप्रमिड, एंटीबॉयोटिक्स, आइवी फ्लूइड, एंटीलमिंटिक्स, एंटीडायरियल, एंटीस्पासमोडिक्स, वैक्सीन, ब्लीचिंग पॉउडर आदि की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

स्वास्थ्य सेवाओं का हो निर्बाध संचालन

बाढ़ संभावित क्षेत्रों में अस्थाई राहत शिविरों के लिये मेडिकल टीम का गठन और संक्रामक रोगों की रोकथाम की पर्याप्त व्यवस्था करने के प्रमुख सचिव ने निर्देश दिए हैं। टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं के निर्बाध संचालन की व्यवस्था और बाढ़ संभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस सेवाओं की आवश्यकता का आंकलन भी कर लें।

निगरानी की रखें पूर्व तैयारी

वरिष्ठ नागरिकों और मधुमेह, उच्च रक्तचाप, लिवर, किडनी, श्वसन रोग से पीड़ित लोगों की निगरानी के लिये व्यवस्था रखी जाये। समस्त अस्पतालों में पेय जल, विद्युत आदि की वैकल्पिक व्यवस्था के प्रबंधन के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशिक्षित रेपिड रेस्पोन्स दल रहें तैयार

आपात स्थिति में त्वरित उपचार उपलब्ध कराने के लिए सहयोगी निजी संस्थाओं, गैर शासकीय संस्थान तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों के सहयोग प्राप्त करने के लिए सामंजस्य स्थापित करके रखा जाए। विभिन्न विभाग वन, पुलिस, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, महिला बाल विकास, मौसम विभाग आदि से समन्वय स्थापित कर बाढ़ संभावित क्षेत्रों के लिए महामारी नियंत्रण के लिए समन्वित योजना बनाई जाए। जिला व विकास खंड स्तर पर आपात स्थिति में प्रशिक्षित चिकित्सा दलों को रेपिड रेस्पोन्स दल के तौर पर सचेत रखा जाए।

मछली उत्पादन में आंध्रा देश का नंबर 1 राज्य

मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाला निकला फिसड्डी

भोपाल। जागत गांव हमार

मछली पालन और जलीय खेती के मामले में आंध्र प्रदेश देश का नंबर 1 राज्य है। देश में कुल मछली पालन और जलीय खेती में इसकी हिस्सेदारी 40.9 फीसदी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल, ओडिशा और बिहार का स्थान आता है। अखिल भारतीय मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। साल 2011-12 में मछली उत्पादन में पश्चिम बंगाल की हिस्सेदारी 24.6 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में घटकर 14.4 प्रतिशत पर पहुंच गई है। हालांकि, ओडिशा और बिहार ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। मछली और जलीय कृषि उप-क्षेत्र का उत्पादन 2011-12 में लगभग 80,000 करोड़ से बढ़कर 2022-23 में लगभग 1,95,000 करोड़ रुपए हो गया। इसी तरह पशुपालन में देश आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत में दूध का उत्पादन समय के साथ-साथ बढ़ रहा है। पशुधन उत्पादन 2011-12 से 2022-23 के बीच लगातार बढ़ा है। इस अवधि के दौरान, दूध, मांस और अंडे के उत्पादन में भी वृद्धि का रुझान दर्ज किया गया।

पशुपालन में कौन राज्य है आगे- आंकड़ों से पता चलता है कि पशुधन उप-क्षेत्र के उत्पादन में दूध, मांस और अंडों की हिस्सेदारी 2022-23 में क्रमशः 66.5 प्रतिशत, 23.6 प्रतिशत और 3.7 प्रतिशत थी, जबकि आधार वर्ष 2011-12 में यह क्रमशः 67.2 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 3.4 प्रतिशत थी। उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने पशुधन उप-क्षेत्र के उत्पादन में लगभग एक चौथाई हिस्सा लिया, जबकि इस अवधि के दौरान तमिलनाडु का उत्पादन तेजी से बढ़ा है।

चीनी उत्पादन में यूपी नंबर-1

इसी तरह साल 2011-12 में चीनी के उत्पादन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 41 प्रतिशत थी, जो 2022-23 में बढ़कर पूरे भारत में चीनी फसलों के उत्पादन के आधे से अधिक हो गई। महाराष्ट्र 19 प्रतिशत के साथ दूसरे स्थान पर रहा, उसके बाद कर्नाटक 8.9 फीसदी, तमिलनाडु 3.9 फीसदी, बिहार 3.3 फीसदी रहा। शेष राज्यों की हिस्सेदारी 11.4 फीसदी रही।

केले ने आम को किया पीछे

जब फलों की बात आती है, तो साल 2022-23 में उत्पादन के मूल्य के मामले में केले ने आम को पीछे छोड़ दिया। केले की हिस्सेदारी 10.9 फीसदी थी, इसके बाद आम की हिस्सेदारी 10 फीसदी थी। 2022-23 के दौरान सब्जियों में, आलू और प्याज ने मिलकर सबसे अधिक उत्पादन में योगदान दिया, जो समूह के 15 प्रतिशत उत्पादन के लिए जिम्मेदार था। फूलों की खेती में 7 प्रतिशत का योगदान था। आंकड़ों से पता चला है कि कृषि, वानिकी और मछली पालन ने 2022-23 में मौजूदा कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन का 18.2 प्रतिशत हिस्सा लिया।

विश्व में भारत का स्थान

भारत कृषि योग्य भूमि (155.37 मिलियन हेक्टेयर) में दुनिया भर में दूसरे स्थान पर है। अनाज के उत्पादन में तीसरा और मूंगफली, फल, सब्जियां, गन्ना, चाय और जूट में दूसरे स्थान पर है। 2020 की नवीनतम उपलब्ध जानकारी के अनुसार, यह दुनिया में मुर्गियों की आबादी के मामले में सातवें स्थान पर है। यह दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है। अंडों के उत्पादन में दूसरे स्थान पर और मांस के उत्पादन में पांचवें स्थान पर है।

2-दो साल में 2-दो करोड़ किसानों ने छोड़ी खेती, जिम्मेदार कौन?

» डॉ राजाराम त्रिपाठी
डॉ राजाराम त्रिपाठी, राष्ट्रीय समन्वयक, अखिल भारतीय किसान महासंघ (आईफा)

पिछले 5 सालों में विभिन्न कारणों से किसान लगातार आंदोलित रहे हैं। पर आज हम ना तो आंदोलनों की बात करेंगे ना किसी सरकार पर कोई आरोप लगाएंगे। हम यहां भारतीय खेती की वतज़्मान दशा–दिशा का एक निष्पक्ष समग्र आंकलन करने की ईमानदार कोशिश करेंगे। इस कार्य में में हम भक्तिकाल के निर्गुण शाखा के मूर्धन्य कवि रहीम 'खानखाना' की भी कुछ मदद ले रहे हैं। आशा है इस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।

देश में खाद्यान्न उत्पादन के घटते–बढ़ते, सच्चे–झूठे आंकड़ों से परे असल हकीकत यही है कि वर्तमान में खेती घाटे का सौदा बन गई है। देश का किसान दिनों दिन बढ़ती कृषि लागत, उत्पादन की मात्रा एवं गुणवत्ता की अनिश्चितता तथा उत्पादन का वाजिब लाभकारी मूल्य न मिल पाने के कारण बेहद परेशान है। पिछले 2–दो सालों में 2–दो करोड़ से ज्यादा किसानों ने खेती छोड़ दिया है।

दूसरी ओर रासायनिक खाद, जहरीली दवाइयों तथा जीएम बीजों ने आज कृषि और किसानों को पयाज़्वरण, धरती एवं मानवता के विरुद्ध खड़ा कर दिया है। जहरीली रासायनिक और घातक कीटनाशकों ने पर्यावरण को ही प्रदूषित नहीं किया, बल्कि मानव स्वारथ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कीटनाशकों की अनेक नई किस्में किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ रही हैं। कृषि वैज्ञानिक इसे 'तकनीकी–थकान' बता रहे हैं। शायद यह तकनीकी असफ्लता को छुपाने के लिए गढ़ा गया एक शालीन नाम है।

आयातित मंहगी कृषि तकनीकें भारतीय किसान के लिए सहारा या बोझ?: इन दिनों सरकार ड्रोन उड़ाकर खेती करने, पॉलीहाउस, ग्रीन हाउस व हाइड्रोपोनिक्स तकनीक को बढ़ावा दे रही है और इसके लिए लाखों करोड़ों का अनुदान भी देती है। लाखों रुपए के अनुदान का लालच दिखाकर इन्हें बेचने वाली कंपनियों के एजेंट भोले–भाले किसानों को हर साल लाखों की कमाई का सब्जबाग दिखाकर अपने जाल में फंसाते हैं और फिर शुरू होता है सब्सिडी तथा बैंक ऋण का खेल, जिसमें हर मोड़ पर घूस का चढ़ावा देकर और लागत की आधी से भी कम कीमत की घटिया दर्जे की सामग्रियां प्रदान की जाती हैं, क्योंकि किसान इन सामग्रियों की तकनीकी मापदंडों एवं गुणवत्ता को नहीं समझ पाता इसलिए बिना जोखिम ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए किसान सहज उपलब्ध सॉफ्ट टार्गेट है। अंत में किसान का हाल भी पतंगे वाला ही होता है। जाहिर है कि हाईटेक अथवा उच्च तकनीकीयुक्त खेती के नाम पर विदेशों की अंधानुकरण की प्रवृत्ति के चलते सरकार तथा किसान दोनों को चूना लगाया जा रहा है। देश के सैंकड़ों नवाचारी किसानों के पास ऐसी–ऐसी परंपरागत टिकाऊ कृषि तकनीकें हैं जो कम से कम लागत में खेती की लाभदायकता बेहतरीन तरीके से बढ़ा सकती हैं जरूरत है उनकी पीठ थपथपाने की और उनके मॉडल को हर किसान के खेतों तक पहुंचाने की, जो कि कोई भी नवाचारी किसान स्वयं नहीं कर पाता।

हरित–क्रांति के दुष्प्रभाव अथवा 'तकनीकी–थकान' का बहाना: खाद्यान्न उत्पादन का सीधा संबंध जनसंख्या से है। भारत ने जनसंख्या वृद्धि में चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। इस बढ़ती हुई जनसंख्या का पेट भरने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया गया और पश्चिमी देशों की तर्ज पर 1966–67 में हरित–क्रांति का अभियान चलाया गया और अधिक अन्न उपजाओ का नारा दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप अधिक उपज प्राप्त करने के लिए रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक खरपतवारनाशकों के कारखाने लगाए गए और आयात भी किया गया। रासायनिक खाद, रासायनिक कीटनाशकों एवं रासायनिक खरपतवारनाशकों का अन्धाधुन्ध व असंतुलित उपयोग प्रारम्भ हुआ। 1966–67 की हरित क्रांति हुए पचास साल से अधिक बीत चुके हैं।

कहा जाता है कि आवश्यक खाध्यान्न के समान उत्पादन के लिए जितनी भूमि की जरूरत होती उसमें से हरित–क्रांति के जरिए 580

लाख हेक्टेयर भूमि बचा ली गयी है। जबकि आज चालीस साल बाद यह सामने आ रहा है कि हमने इससे दोगुनी भूमि पर्यावरणीय दृष्टि से बर्बाद कर दी है, जिसका निकट भविष्य में कोई उपचार भी दिखाई नहीं देता।

कीटनाशकों ने पर्यावरण को ही प्रदूषित नहीं किया, बल्कि मानव तथा सभी जीवों के लिए स्वारथ्य के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर दिया है। कीटनाशकों की अनेक नई किस्में किसानों के लिए बर्बादी लेकर आ रही हैं। कृषि वैज्ञानिक इसे 'तकनीकी थकान' बता रहे हैं। शायद यह तकनीकी असफलता को छुपाने के लिए दिया गया एक शालीन नाम है।

खेती और पानी: पानी के मोर्चे पर हमने अपनी लगातार गलतियों से भी कोई सबक नहीं सीखा और ज्यादातर राज्यों में हम बेहद खतरनाक स्थिति में पहुंच चुके हैं। कई राज्यों में भूजल लगभग समाप्त हो गया है और पानी के लिए त्राहि–त्राहि मची हुई है। सिंचाई के क्षेत्र में अव्वल, पांच नदियों के प्रदेश एवं हरित क्रांति का पुरोधा कहे जाने वाले पंजाब का मामला देखिए यहां 138 ब्लाकों में से 108 पहले भी भूजल के स्तर के मामले में डार्क जोन घोषित कर दिए गये हैं। इन क्षेत्रों में भूजल के दोहन का स्तर खतरे के निशान 80 प्रतिशत को भी पारकर 97 प्रतिशत तक पहुंच गया।

उत्तर प्रदेश में भी स्थिति बहुत नाजुक है। केंद्रीय भूजल बोर्ड ने अधिक दोहन के कारण भूजल का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंचाने वाले 22 ब्लाकों की पहचान की है। इनमें से 19 ब्लाक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। गन्ना उत्पादक किसान, जो मिलों के साथ गन्ना आपूर्ति का बांड भरते हैं, उनकी गन्ने की फसल हर साल 240 क्यूबिक मीटर पानी पी जाती है। गेहूं और चावल के मुकाबले यह करीब ढाई गुना अधिक है। गिरता भूजल स्तर जमीन को अनुत्पादक और बंजर बना देता है। राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भू उपयोग नियोजन ब्यूरो का अनुमान है कि देश की कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 12 करोड़ हेक्टेयर भूमि अलग–अलग तरह से उत्पादकता ह्रास का शिकार हो रही है।

शुरुआती दौर में रासायनिक खाद ने पैदावार जरूर बढ़ाई, लेकिन इसके साथ–साथ कृषि भूमि क्रमशः रोगग्रस्त और अनुपजाऊ होते चली गयी। पर्यावरण के विनाश के निशान दृष्टिगोचर थे, लेकिन खेतों की कम हो रही उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद कंपनियों के खाद से खेत पाट दिए। जैसे इतना ही काफी न हो, भूजल में नाइट्रेट मिलते जाने से जन–स्वास्थ्य के लिए भी खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब यह साबित हो गया है कि दस साल पहले जितनी फसल लेने के लिए उस समय की तुलना में दोगुनी खाद डालनी पड़ रही है। इससे किसान कर्ज के जाल में फंस रहे हैं।

हालिया अध्ययन में खाद की खपत और उत्पादन के बीच नकारात्मक सह–संबंध के बारे में साफ–साफ बताया गया है। जिन क्षेत्रों में खाद की खपत कम रही है वहां आज फसल की उपज अधिक है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि खाद कंपनियों को कभी ऐसे निर्देश नहीं दिए गये कि वे मिट्टी के पोषक तत्वों में सतुलन का ध्यान रखें, ताकि विविध प्रकार से भूमि में रासायनिक तत्वों का जमावड़ा न हो।

आंख मूंदकर विदेशों से आयातित तकनीकों को स्वीकार कर लेने की प्रवृत्ति किसानों पर बहुत भारी पड़ रही है। वर्तमान में भारतीय खेती अपने कठिनतम दौर से गुजर रही है, पर यही वह महत्वपूर्ण समय भी है जब हम मिल–बैठकर अपनी खेती की इस दुरावस्था के असल कारकों की सही पहचान कर उनके निवारण हेतु सही रणनीति बनाकर देश की खेती एवं किसानों का भविष्य संवार सकते हैं। आज जरूरत है भारतीय तकनीकों के विकास की, जो सस्ती, टिकाऊ, उपयोगी और पर्यावरण हितैषी हों।

इसलिए लेख का अंत रहीम की इस दोहे के साथ करना

मौसम की मार झेलता 80प्रतिशत सीमांत किसान

जलवायु परिवर्तन की वजह से मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिसका सीधा असर देश के किसानों पर भी पड़ रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में प्रतिकूल जलवायु घटनाओं के कारण भारत में 80 प्रतिशत सीमांत किसानों को फसल का नुकसान उठाना पड़ा है। फ़ोरम ऑफएंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट द्वारा डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट के सहयोग से किए गए सर्वेक्षण में 21 राज्यों के 6,615 किसान शामिल थे, जिसमें बताया गया है कि 41प्रतिशत किसान बारिश से, 32प्रतिशत सूखे से और 24 प्रतिशत किसान लेट मॉनसून से परेशान हैं।

रिसर्च से पता चला है कि फसल के नुकसान का प्राथमिक कारण सूखा (41 प्रतिशत), बहुत ज्यादा या बेमौसम बारिश सहित अनियमित वर्षा (32 प्रतिशत) और मॉनसून का समय से पहले वापस चले जाना या देर से आना (24 प्रतिशत) है। रिपोर्ट के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल लगभग 43 प्रतिशत किसानों ने अपनी खड़ी फसलों का कम से कम आधा हिस्सा खो दिया है।

असमान वर्षा के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित चावल, सब्जी और दाल की फसलें हुई है। वहीं, उत्तरी राज्यों में धान के खेत अक्सर एक सप्ताह से अधिक समय तक जलमग्न रहते हैं, जिससे नए लगाए गए पौधे नष्ट हो जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में कम बारिश के कारण चावल, मक्का, कपास, सोयाबीन, मूंगफली और दालों जैसी विभिन्न फसलों की बुवाई में देरी हुई है। हालांकि, इस रिपोर्ट में तापमान से होने वाले बदलावों के प्रभाव को शामिल नहीं किया गया है।

साल 2022 में भारत में हीटवेव के शुरुआती प्रकोप ने गेहूं की फसल को प्रभावित किया था, जिसकी वजह से गेहूं का उत्पादन साल 2021 के 109.59 मिलियन टन से घटकर 107.7 मिलियन टन रह गया था। इस वजह से दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गेहूं उत्पादक देश भारत को निर्यात पर प्रतिबंध लगाना पड़ा था। गर्मी ने साल 2023 में फि्र से गेहूं के उत्पादन को प्रभावित किया, जिससे आधिकारिक लक्ष्य लगभग 3 मिलियन टन कम हो गया।

रिपोर्ट में हुआ खुलासा: साल 2021 की क्लाईमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में बताया गया है कि चावल के उत्पादन में 10 से 30 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है और 1 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान वृद्धि की वजह से मक्का का उत्पादन 25 से 70 प्रतिशत तक घट सकता है। सीमांत किसान, जिनके पास एक हेक्टेयर से भी कम भूमि है वे भारत के कृषि क्षेत्र का सबसे बड़ा हिस्सा हैं, जो सभी किसानों का 68.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन फसल क्षेत्र का केवल 24 प्रतिशत ही उनके पास है।

फोरम ऑफएंटरप्राइजेज फॉर इक्विटेबल डेवलपमेंट के अध्यक्ष संजीव चोपड़ा का कहना है कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर भारत में देखने को मिला है। इस साल दिल्ली–एनसीआर और पूरे देश में भीषण गर्मी का पड़ना इस बात का स्पष्ट संकेत है। इसे रोकने के लिए जलवायु–अनुकूल कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, आजीविका में विविधता लाना और वित्तीय सेवाओं और तकनीकी सलाह की पहुंच में सुधार करने की आवश्यकता है। सीमांत किसानों में से 83 प्रतिशत पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत आते हैं, लेकिन सिर्फ35 प्रतिशत के पास फ्सल बीमा पहुंचता है और मात्र 25 प्रतिशत को समय पर वित्तीय ऋ्ण मिलता है।

सर्वेक्षण में पाया गया है कि मौसम की घटनाओं से प्रभावित दो–तिहाई सीमांत किसानों ने जलवायु–अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाया है, जिसमें बुवाई के समय और तरीकों, फसल की अवधि और जल एवं रोग प्रबंधन रणनीतियों में बदलाव करना शामिल है। हालांकि, इन पद्धतियों को अपनाने वाले 76 प्रतिशत लोगों को ऋण सुविधाओं की कमी, भौतिक संसाधनों की कमी, सीमित ज्ञान, कम भूमि और ज्यादा लागत जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है।

जबकि 21 प्रतिशत सीमांत किसानों के पास उनके गांव के 10 किलोमीटर के अंदर कोल्ड स्टोरेज है, लेकिन मात्र 15 प्रतिशत ने इन सुविधाओं का उपयोग किया है। वहीं 48 प्रतिशत के पास उनके गांव के 10 किलोमीटर के अंदर कस्टम हायरिंग सेंटर है, लेकिन सिर्फ 22 प्रतिशत ने इन केंद्रों से उपकरण किराए पर लिए हैं।

जीव-जन्तु और उनका अपना मौसम विज्ञान

» बाबूलाल दाहिया

मनुष्य ने हर क्षेत्रों में तरक्की की है। उसके दो अदद फुर्सत के हाथ और एक अदद विलक्षण बुद्धि ने जल, थल, अंतरिक्ष किसी को भी अपनी दखलन्दाजी से महफूज नहीं छोड़ा। उसका विज्ञान 24 य 48 घण्टे पहले ही बता देता है कि समुद्र में तेज हवाएं आएंगी इसलिए नाविक गहरे समुद्र में मछली मारने मत जाए? कब वर्षा होगी या बर्फ पड़ेगी? यह सब सटीक मौसम सम्बंधित ज्ञान प्रसारित कर वह लोगों को सचेत करता रहता है। परन्तु एक विज्ञान पशु पक्षियों में भी है जो उनके गुण सूत्रों में ही पीढ़ियों से मौजूद है। और समय–समय पर उनकी छठी इंद्री उन्हें निर्देश देती रहती है कि तुम्हे यह करना है और यह नही करना? हमें याद है कि 60 के दशक तक हमारे गाँव में जब खूब घना जंगल था तब अगर पहाड़ के खेतों की तरफजुताई होती तो हल में चल रहे हमारे बैल सूर्यास्त होने के 2–3 घण्टा पहले से ही कान खड़ा कर बार–बार रुक जाते। जैसे हल चलाने वालों को इशारा देकर समझा रहे हों कि भाई अब तू अपना हल ढील और शीघ्र ही यहां से हमें ले चल। क्योकि बाघ तेंदुए के बिचरण का समय होने वाला है? और फिर जैसे ही हल ढिलता तो वे वहां से तुरन्त रवाना हो जाते। रास्ते में कितनी भी अच्छी घास लगी हो वह मुँह तक न मारते। इसके विपरीत जब वह गांव के मैदानी भाग वाले खेतों में होते तो हल से ढिल जाने के पश्चात भी रात्रि में घन्टों घास चरते रहते।

बया नामक पक्षी को देखिए अगर वह पेड़ की टहनी के बिल्कुल किनारे अपना घोंसला बनाए तो उसका संकेत है कि इस साल वर्षा कम होगी। किन्तु वही बया पक्षी अगर टहनी के मध्य घने पत्तों के नीचे घोंसला बनाता है तो वह अधिक वर्षा का परिचायक होता है। नदियों के किनारे बसने वाले केवट लोग जिनकी आजीविका ही नदियों से जुड़ी रहती है हमेशा यह गुरज्ञान वे बया पक्षी से ही लेते हैं कि इस वर्ष उन्हें नदी से कितनी ऊँचाई पर अपनी झोपड़ी बनाकर रहना चाहिए? उनका घोंसला जितनी ऊँचाई तक होता है उसका अर्थ यह होगा कि इस वर्ष नदी में इससे ऊपर बाढ़ नही आएगी। इसी तरह एक पक्षी टिटिहरी है जो उड़ तो सकता है पर उसके पैरों की बनावट पेड़ों में बैठने लायक नही होती, अस्तु वह जब भी बैठेगा तो जमीन में ही और जमीन में ही अपने अंडे भी देता है। किन्तु साँप या कौआ आदि कोई उसके अंडे को खा न पाए? इसलिए वह सूखे नाले के ठीक मध्य में पाल बना अपने अंडे रखता है। उसका अपना रंग तो मटमैला होता ही है, किन्तु उसके अंडों का रंग भी नाले के बालू या मिट्टी की तरह ही मटमैले रंग का होता है। इससे कोई जन्तु वनस्पति रहित उस सूने नाले के मध्य नहीं जाते और अंडे से सुरक्षित बच्चे आराम से निकल आते हैं। परन्तु वह अंडे तभी देगा जब उसके मष्तिष्क का कम्प्यूटर बता रहा होता है कि अंडे से बच्चे निकल कर उड़ने तक अभी नाले में बहने लायक तेज बारिश नहीं होगी?

इस तरह सभी जीव जन्तु प्रकृति के नियमों में बंधे हैं। अस्तु मनुष्य को इन तमाम जीव जन्तुओं से शिक्षा लेनी चाहिए कि कम से कम ऐसा काम न करे जो समस्त जीव जगत को ही खतरे में डाल दे।

नर्सरी में पौध तैयार करने से लेकर बिक्री तक की छूट

चंदन की खेती से किसानों को होगी लाखों की कमाई

चंदन के बीज अप्रैल-मई और नवंबर दिसंबर साल में दो बार गिरते हैं

भोपाल। जागत गांव हमार

चंदन विष व्यापत नहीं लिपटत रहत भुजंग ये रहीम दास जी की लिखी एक पंक्ति है जिसमें चंदन के पेड़ का महिमामंडन किया गया है। चंदन का पेड़ आपने भले ही ना देखा हो लेकिन इसके गुण और उपयोगिता के किस्से खूब सुने होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि चंदन का पेड़ बेशकीमती होता है और इसकी मांग बहुत ज्यादा है। हमारे देश में चंदन के बारे में खूब लिखा और सुना गया है लेकिन चंदन की खेती की बात आए तो अधिकांश लोग बहुत कम जानते हैं। अगर आप चंदन की खेती या चंदन का पेड़ लगाना चाहते हैं तो इससे जुड़ी सारी जानकारी इस खबर में मिल सकती है। इस खबर में हम आपको चंदन का पौध तैयार करने से लेकर बेशकीमती पेड़ बनने तक के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं।

ऐसे तैयार होता है नर्सरी में पौध- चंदन का पौध तैयार करने के लिए चंदन के बीजों को खास तरीके से प्रोसेस किया जाता है। चंदन के बीज पुराने चंदन के पेड़ों से गिरते हैं। केंद्रीय हाईटेक नर्सरी हसदो वनमंडल मनेंद्रगढ़ (छत्तीसगढ़) ने किसानतक को बताया कि चंदन के बीज अप्रैल- मई और नवंबर दिसंबर साल में दो बार गिरते हैं। इन बीजों को इकट्ठा करके पानी में करीब 2-3 दिनों तक भिगोकर रखा जाता है जिससे बीजों की बाहरी और सख्त परत निकल जाती है जिसे बीज कोट कहते हैं। इसके बाद इन बीजों को सुखाया जाता है। सूखे बीजों को रोपाई से 12 घंटे पहले गुनगुने पानी में फिर से भिगो कर अच्छी तरह सुखाया जाता है।

कतारबद्ध तरीके से बीज रोपें

अब बीजों को लगाने के लिए मिट्टी का एक बेड तैयार करना होता है। मिट्टी से तैयार इस बेड का अनुपात 2:1:1 होता है (2 टोकरी मिट्टी-1 टोकरी रेत-1 टोकरी वर्मी या गोबर कंपोस्ट)। इस बेड की ऊंचाई 20-25 सेंमी रखी जाती है। इस बेड में उंगली से गड्ढा करके कतारबद्ध तरीके से बीज रोपे जाते हैं। इस वक्त नर्सरी में 30-40 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है। इसके बाद हर तीसरे दिन इस बेड में फव्वारे से हल्की सिंचाई की जाती है। 45 दिनों में बीजों से पौधे का अंकुरण होने लगता है।

पौध तैयार होने के बाद की प्रक्रिया

लगभग 45 दिनों के बाद अंकुरित बीजों को 2:1:1 अनुपात वाली मिट्टी के मिश्रण से भरे पॉलीथीन बैग में ट्रांसफर किया जाता है। इन पौधों को पॉलीथीन में लगाते समय हर पौधे के साथ अरहर का पौधा लगाना जरूरी होता है। नर्सरी में मौजूद एक्सपर्ट्स ने बताया की चंदन का पौधा परजीवी होता है जो नाइट्रोजन का संचय नहीं कर पाता है। नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए चंदन के पौधे के साथ अरहर का पौधा लगाना बहुत जरूरी होता है।

यहां से खरीद सकते हैं चंदन के पौधे

पौधा तैयार होने के बाद इससे तेल निकाला जाता है जो बेशकीमती होता है। इस तेल का उपयोग अगरबत्ती, इत्र और कई महंगे कॉस्मेटिक आइटम बनाने में किया जाता है। आप भी चंदन का पेड़ लगाना चाहते हैं तो केंद्रीय हाईटेक नर्सरी हसदो वनमंडल मनेन्द्रगढ़ (छत्तीसगढ़) से पौध खरीद सकते हैं। प्रति पौध की कीमत 30 रुपए बताई गई है।

खेतों में चंदन का पेड़ लगाने की विधि

अधिकांश लोग चंदन की खेती करके तगड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन इसकी खेती के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। हमने आपको नर्सरी में पौध तैयार करने की विधि बताई है। अब घर या खेत में चंदन का पेड़ लगाने के बारे में बताते हैं। चंदन के पेड़ लगाने के लिए 3*3 सेमी. गहरा गड्ढा खोदें। रोपाई के समय इस गड्ढे में मिट्टी के साथ रेत और कार्बनिक पदार्थों से भरी खाद मिलाकर पौधे के चारों ओर भरें और हल्का पानी डालें। इस पौधे के साथ अरहर का पौधा लगाना ना भूलें। शुरुआत के 3-4 सालों में चंदन के पौधे की खास देखभाल करने की जरूरत होती है। ध्यान रहे पौधे मिट्टी को सूखने नहीं देना है इसके साथ ही अधिक जल भराव करने से भी बचें। पौधे के आसपास अनावश्यक रूप से उग रहे घास-फूस की सफाई करते रहें। जब पौधा बढ़ने लगे तो एक बांस गाड़ कर इसे सहारा दें ताकि पौधा सीधा बढ़ता रहे। चंदन के पौधे को तैयार होने में लगभग 30-40 सालों का समय लगता है तब इससे सुगंध आती है। चंदन की सुगंध आने के बाद ये पौधा बेंच सकते हैं जिसकी कीमत लाखों में हो सकती है।

दूध उत्पादकों में पांच प्रजाति की सबसे ज्यादा मांग

भारत में पाई जाती हैं 50 से अधिक नस्ल की गाय

भोपाल। भारत एक ऐसा देश है जहां देशी गोजातीय पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। यहां गायों की 50 से अधिक और भैंसों की 17 से अधिक नस्लें हैं। ये नस्लें कई पीढ़ियों में विकसित हुई हैं। कुछ देशी नस्लों के वयस्क नर पशु अपने भार ढोने के गुणों के लिए जाने जाते हैं। तो इनमें से कुछ नस्लें अपने अधिक दूध और वसा उत्पादन के लिए जानी जाती हैं। हालांकि, उचित देखभाल और नस्लों के सही चयन के अभाव में समय के साथ इन पशुओं की उत्पादकता में कमी आई है। जिसे सुधारना बहुत जरूरी है। शायद यही वजह है कि इतनी सारी नस्लों के बीच पशुपालकों द्वारा कुछ ही नस्लों को महत्व दिया जाता है। इस कड़ी में आइए जानते हैं गायों की उन 5 नस्लों के बारे में जिनकी मांग सबसे ज्यादा है।

गिर नस्ल की गाय

गिर नस्ल की गाय का मूल स्थान गुजरात है। गिर गाय को भारत की सबसे अधिक दूध देने वाली गाय माना जाता है। यह गाय एक दिन में 50 से 80 लीटर दूध देती है। यही कारण है कि पशुपालकों के द्वारा गाय की इस नस्ल को सबसे अधिक पसंद किया जाता है। इस गाय के थन बहुत बड़े होते हैं। इस गाय का मूल स्थान काठियावाड़ (गुजरात) के दक्षिण में गिर का जंगल है, जिसके कारण इसका नाम गिर गाय पड़ा है। भारत के अलावा विदेशों में भी इस गाय की काफी मांग है। इन गायों को मुख्य रूप से इजरायल और ब्राजील में भी पाला जाता है।

साहीवाल नस्ल| साहिवाल भारत की सबसे अच्छी नस्ल है। इसका मूल स्थान पंजाब और राजस्थान है। यह गाय मुख्य रूप से हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। यह गाय सालाना 2000 से 3000 लीटर दूध देती है, जिसके कारण ये दूध व्यवसायी इन्हें बहुत पसंद करते हैं। एक बार यह ब्याती है, तो करीब 10 महीने तक दूध देती है। अगर इसकी अच्छी तरह से देखभाल की जाए तो यह कहीं भी रह सकती है।

राठी नस्ल| इस नस्ल का मूल स्थान राजस्थान है। भारतीय राठी गाय की नस्ल अधिक दूध देने के लिए जानी जाती है। राठी नस्ल का राठी नाम राठस जनजाति के नाम से लिया गया है। यह गाय राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर इलाकों में पाई जाती है। यह गाय प्रतिदिन 8-10 लीटर दूध देती है।

लाल सिंधी नस्ल| गाय की यह नस्ल पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु में पाई जाती है। यह लाल गाय अपने उच्च दूध उत्पादन के लिए जानी जाती है। अपने लाल रंग के कारण, इसका नाम लाल सिंधी गाय रखा गया। पहले यह गाय केवल सिंध क्षेत्र में पाई जाती थी। लेकिन अब यह गाय पंजाब, हरियाणा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा में भी पाई जाती है। भारत में इनकी संख्या बहुत कम है। साहीवाल गायों की तरह लाल सिंधी गाय भी सालाना 2000 से 3000 लीटर दूध देती है।

नागोरी नस्ल| गाय की यह नस्ल राजस्थान के नागौर जिले में पाई जाती है। इस नस्ल के बैल अपनी भार वहन क्षमता के विशेष गुण के कारण बहुत प्रसिद्ध हैं। निमरी (मध्य प्रदेश) निमरी का मूल स्थान मध्य प्रदेश है। इसका रंग हल्का लाल, सफेद, लाल, हल्का बैंगनी होता है। इसकी त्वचा हल्की और ढीली होती है, माथा उभरा हुआ, शरीर भारी, सींग नुकीले, कान चौड़े और सिर लंबा होता है।

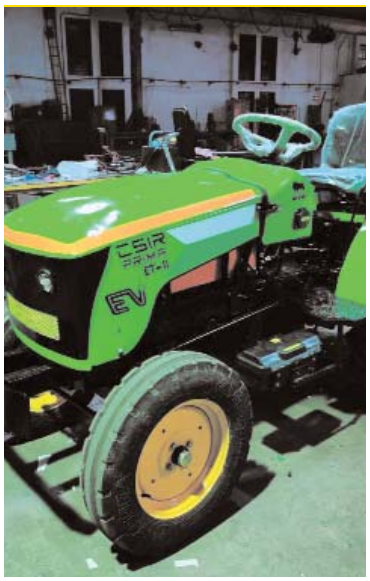

विकसित किया कॉम्पैक्ट और किफायती ट्रैक्टर

सीमांत किसानों के लिए सीएसआईआर का तोहफा

भोपाल।

भारत में छोटे और सीमांत किसानों की संख्या अधिक है। यहां पर 80 प्रतिशत छोटे और सीमांत किसान हैं। जिनके पास छोटी जोत की जमीन है। इस 80 प्रतिशत आबादी का एक बड़ा हिस्सा आज भी अपने खेतों की जुताई के लिए पारंपरिक तरीकों पर ही निर्भर है। वो जुताई के लिए बैल और भैंसों का इस्तेमाल करते हैं।

इनका रखरखाव, इनके मेंटेनेंस का खर्च और फिर इससे किसानों को जो रिटर्न मिलता है वो काफी कम है। हालांकि हालांकि पावर टिलर बैलों से चलने वाले हल की जगह ले रहे हैं, लेकिन उन्हें चलाना परेशानी भरा है। जबकि बड़ा ट्रैक्टर छोटे किसानों के लिए अनुपयुक्त हैं। अधिकांश छोटे किसान इसके रखरखाव का खर्च उठाने में सक्षम नहीं है। किसानों को इन परेशानियों और चुनौतियों से मुक्ति दिलाने के लिए और उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए सीएसआईआर-केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-सीएमईआरआई) ने डीएसटी के एसईईडी प्रभाग के सहयोग से सीमांत और छोटे किसानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए कम हॉर्स पावर रेंज का एक कॉम्पैक्ट, किफायती और आसानी से चलने योग्य ट्रैक्टर विकसित किया है। छोटे और सीमांत किसानों के लिए एक नया विकसित कॉम्पैक्ट, किफायती और आसानी से चलने वाला ट्रैक्टर उन्हें लागत कम रखते हुए कृषि उत्पादकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। एक एमएसएमई ने किसानों को आपूर्ति के लिए ट्रैक्टरों के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाई है।

किसानों तक लाभ पहुंचाने की कोशिश

उन्होंने कई मौजूदा स्त्रोत्र के बीच इस तकनीक को बढ़ावा दिया है, और इस तकनीक के लिए विशेष रूप से नए स्त्रोत्र बनाने के प्रयास किए गए हैं। सीएसआईआर-सीएमईआरआई बड़े पैमाने पर विनिर्माण के लिए स्थानीय कंपनियों को इसका लाइसेंस देने पर भी चर्चा कर रहा है, ताकि इसका लाभ स्थानीय किसानों तक पहुंच सके। ट्रैक्टर को 9 एचपी डीजल इंजन के साथ विकसित किया गया है जिसमें 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स स्पीड, 540 आरपीएम पर 6 स्प्लिन के साथ पीटीओ है। ट्रैक्टर का कुल वजन लगभग 450 किलोग्राम है, जिसमें आगे के पहिए का आकार 4.5-10 है और पीछे के पहिये का आकार 6-16 है। व्हीलबेस 1200 एमएम है, ग्राउंड क्लीयरेंस 255 मिलीमीटर और टर्निंग रेडियस 1.75 मीटर है।

किसानों को मिलेगी राहत

इससे खेती में तेजी आएगी, बैलगाड़ी से खेती करने में लगने वाले कई दिनों की तुलना में खेती कुछ ही घंटों में पूरी हो जाएगी और किसानों की पूंजी और रखरखाव लागत भी कम हो जाएगी।इसलिए, किफायती कॉम्पैक्ट ट्रैक्टर छोटे और सीमांत किसानों के लिए बैल चालित हल की जगह ले सकता है। इस तकनीक का प्रदर्शन आस-पास के गांवों और विभिन्न निर्माताओं के सामने किया गया। रांची स्थित एक एमएसएमई ने ट्रैक्टर के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करके इसके निर्माण में रुचि दिखाई है। वे विभिन्न राज्य सरकार निविदाओं के माध्यम से किसानों को सब्सिडी दरों पर विकसित ट्रैक्टर की आपूर्ति करने की योजना बना रहे हैं।

जुलाई में करे सब्जियों की खेती, मिलेगी बंपर पैदावार, हो जाएंगे मालामाल

मिलेगी बंपर पैदावार, हो जाएंगे मालामाल

भोपाल। कम समय में ज्यादा फायद कमाने के लिए किसान अब पारंपरिक खेती को छोड़ कर गैर-पारंपरिक खेती करना पसंद कर रहे हैं। किसान कम समय में अधिक लाभ कमाने के लिए सब्जियों की खेती करना पसंद करते हैं। ऐसे में जुलाई माह को सब्जी की खेती के लिए काफी अच्छा माना जाता है, क्योंकि इनकी खेती से अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। जुलाई माह में करें इन सब्जियों की खेती।

खीरा- जुलाई के महीने में खीरा की खेती किसानों के लिए काफी लाभदायक मानी जाती है। बता दें, खीरे की फसल से बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के लिए सूरज की रौशनी के साथ-साथ भरपूर पानी की आवश्यकता होती है। किसान मानसून में खीरे की खेती करके मोटी कमाई सकते हैं, इसके लिए उन्हें इसकी उन्नत किस्मों की बुवाई करनी चाहिए। जुलाई में खीरे की बुवाई के लिए आपकी इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं, इनमें-पूसा उदय,पूसा संयोग, पूसा बरखा, स्वर्ण अगेती और स्वर्ण पूर्णिमा आदि प्रमुख हैं। इसके अलावा, किसान खीरे की विदेशी हाइब्रिड किस्में को लगाकर भी काफी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।

चौलाई- खरीफ सीजन की चौलाई एक प्रमुख नकदी फसल है, इसे गर्मी और बारिश दोनों मौसम में लगाने से काफी अच्छा खासा उत्पादन प्राप्त होता है। आपको बता दें। चौलाई एक औषधीय फसल है, इसकी पत्ती, डंठल और जड़ का उपयोग दवाएं बनाने के लिए किया जाता है। किसान जुलाई माह में चौलाई की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए इसकी उन्नत किस्मों का चयन कर सकते हैं। इसकी उन्नत किस्मों में छोटी चौलाई, बड़ी चौलाई, कपिलासा, सुवर्णा, अन्नपूर्णा, आर एम ए 4, पूसा लाल और गुजरती अमरंथ दो शामिल है।

भिंडी- मानसून सीजन में भिंडी की खेती किसानों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। भिंडी की खेती वैसे तो किसी भी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है, लेकिन बारिश के मौसम में जल निकासी वाली मिट्टी रेतीली और चिकनी मिट्टी में इसकी खेती करके बंपर पैदावर प्राप्त की जा सकती है। किसानों को भिंडी की फसल की तुड़ाई अधपकी अवस्था में ही कर लेनी चाहिए। भिंडी की फसल से तगड़ा उत्पादन प्राप्त करने के लिए आप इसकी उन्नत किस्मों का भी चयन कर सकते हैं, इनमें - वर्षा उपहार, पूसा सावनी, पूसा मखमली, पूसा ए-4, अर्का अभय, परभनी क्रांति, वीआरओ-6 और हिसार उन्नत आदि शामिल है। इसके अलावा, जुलाई माह में आप लाल भिंडी की खेती करके काफी अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं।

मिर्च और धनिये की खेती

मानसून में किसान अच्छी कमाई के लिए धनिया और मिचऱ् की खेती कर सकते हैं, ये फसल बरसात के समय काफी अच्छी तरह से बढ़ती हैं। इन फसलों को अधिक देखरेख भी आवश्यकता नहीं होती है। इनकी खेती के लिए बलुई दोमट या लाल मिट्टी को उपयुक्त माना जाता है।

पालक और तोरई की खेती

मानसून में पालक और तोरई की खेती करना किसानों के लिए काफी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि बारिश के मौसम में किसान इन फसलों की खेती कम लागत में कर पाते हैं। इन फसलों के लिए दोमट मिट्टी काफी अच्छा माना जाता है।

बीन्स की खेती

जुलाई-अगस्त का महीना बीन्स की खेती के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। इसका पौधा बेलदार होता हैं, इसलिए आपको इसके पौधे की बुवाई किसी दीवार या पेड़ के आसपास ही करनी चाहिए। मानसून में इसका पौधा सही से विकसित होता है और इसके फल का भी उत्पादन बढ़ता है।

बरसात में रखें इन बातों का ध्यान

किसानों को बरसात के मौसम में खेती करने से पहले अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण करवा लेना चाहिए। फसल की बुवाई से पहले सही बीज का चुनाव करना चाहिए। किसानों को फसल में खरपतवार नियंत्रण और सिंचाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए।

टमाटर- टमाटर की खेती के लिए मानसून सीजन अच्छा माना जाता है, बढ़ती कीमतों के बीच किसानों के लिए इसकी खेती फायदे का सौदा हो सकती है। टमाटर की खेती से बंपर उत्पादन प्राप्त करने के लिए किसानों को इसकी उन्नत किस्मों का चयन करना चाहिए, देसी किस्मों में - पूसा रूबी, पूसा शीतल, पूसा-120, पूसा गौरव, अर्का विकास, अर्का सौरभ और सोनाली शामिल है। वहीं इसकी हाइब्रिड किस्मों में - पूसा हाइब्रिड-1, पूसा हाइब्रिड-2, पूसा हाइब्रिड-4, रश्मि और अविनाश-2 आदि शामिल है।

करेला- मानसून में करेले की खेती अच्छी जल निकासी वाली दोमद मिट्टी में करना किसानों के लिए काफी लाभकारी होता है। बता दें, देश में करेले की खपत सब्जी के साथ-साथ औषधि रूप से भी की जाती है, जिस वजह से इसकी काफी अधिक मांग रहती है। करेले की खेती करने के लिए आपको प्रति एकड़ के हिसाब से 500 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, लेकिन नर्सरी में इसके पौधे को तैयार करने के लिए कम से कम बीजों की जरूरत पड़ती है। किसान जुलाई में इसकी उन्नत किस्मों का चयन करके मोटी कमाई कर सकते हैं, इसकी प्रमुख किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा हाइब्रिड 2, पूसा विशेष, अर्का हरित और पंजाब करेला 1 शामिल है।

नरसिंहपुर कृषि विज्ञान केन्द्र द्वारा नई पहल

अब बीज बम से आएगी हरियाली

नरसिंहपुर। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम के मार्गदर्शन में मिट्टी और केंचुआ खाद्य गोबर में पानी मिलाकर एक गेंद या गोला बनाकर स्थानीय जलवायु और मौसम के अनुसार उस गोले में जंगली पौधों की बीज जैसे- हर्रा, बहेरा, रीठा, महुआ, अमलतास, नीम, बीजा, अंजन, करंज, तेन्दू, आचार इत्यादि बीजों को जो कि बिना देखभाल के विपरीत परिस्थिति में भी जमीन पर आसानी से लग जातें है। इस बीज बम को जंगल में या किसी भी खाली जगह में फेंक दिया जाता है या अनुकूल स्थान पर छोड दिया जाता है। अनुकूल परिस्थितियों में बीजों में अंकुरण होकर वृक्ष तैयार हो जाते है इसे बीज बम नाम इसलिए दि गया है ताकि इस तरह के अटपटे नाम से लोग आकर्षित हो और इस बारे में जानने का प्रयास करें। उन्होंने कहा लोगों ने ऑक्सीजन के महत्व को समझा है यह ऑक्सीजन हमें प्राकृतिक रूप से पेड- पौधों द्वारा नि:शुल्क प्राप्त होती है परंतु अंधाधुंध विकास की होडके परिणाम स्परूप निरंतर वृक्षों की कटाई से हमारे ऑक्सीजन दाता की संख्या में तेजी से कमी आ रही है। वर्तमान समय में ऑक्सीजन की कमी के कारण त्राही त्राही मची हुई है। अत: पर्यावरण सम्पूणऱ् मानव जाति पशु पक्षी के संरक्षण हेतु वृक्षारोपण किया जाना नितांत आवश्यक है।

बीज बम के द्वारा वृक्षारोपण की एक शुन्य बजट आधारित छोटी पहल कारगर साबित हो सकती है। कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर के वैज्ञानिकों द्वारा वृक्षारोपण हेतु बीजो के प्रसारण के लिए सीड बॉल या जिसे बीज बम कहते हैं। बनाया जा रहा है जिसका प्रयोग मानसून आने के पश्चात जुलाई में किया जाना है। जापान और मिश्र जैसे देशों में यह तकनीकी सीड बॉल के नाम से सदियों पहले से परंपरागत रूप से चलती रही है। यह नामकरण अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल रहा है। कृषि विज्ञान केन्द्र नरसिंहपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. विशाल मेश्राम ने बताया कि यह एक शून्य बजट अभियान है। इसमें मिट्टी और गोबर को पानी के साथ मिलाकर एक गोला बना दिया है और स्थानीय जलवायु और मौसम के अनुसार उस गोले में कुछ बीज डाल दिये जाते हैं। इस बम को जंगल में कहीं भी अनुकूल स्थान पर छोड़ दिया जाता है। बीज बम में अल्पकालीन और दीर्घकालीन दोनों तरह के बीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्पकालीन बीजों में कद्दू, मटर, लौकी, मक्का जैसी मौसमी सब्जियों और अनाजों के बीज शामिल हैं, जो एक या दो महीने में खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दीर्घकालीन बीजों में स्थानीय जलवायु के अनुसार आम, जामुन, शहतूत, नीम, मुनगा, कटहल आदि के बीज शामिल किये जा सकते हैं। विकास कार्यों के चलते अब हरे-भरे पौधे और वृक्ष लुप्तप्राय: वस्तु बनते जा रहे हैं। यूएनईपी की एक रिपोर्ट बताती है कि बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में हमारी धरती की सतह (भूमि) पर लगभग 7.0 अरब हेक्टेयर भूमि पर वन थे और 1950 तक वन्यावरण घटकर 4.8 अरब रह गया था। अब आंकड़े बता रहे हैं कि वन घटकर 2.35 अरब ही रह गए हैं। डराने वाला तथ्य है कि प्रतिवर्ष 7.3 मिलियन हेक्टेयर उष्ण कटिबंधीय वन समाप्त हो रहे हैं।

नए पदस्थ कृषि विस्तार अधिकारियों का एक दिवसीय दिया गया प्रशिक्षण

शिवपुरी। जागत गांव हमार

गत दिवस शिवपुरी कलेक्टर के निर्देशानुसार उपसंचालक कृषि के समन्वय में शिवपुरी जिले के विभिन्न विकासखंडों में पदस्थ नए कृषि विस्तार अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी के सभागार कक्ष में आयोजित किया गया। जिसमें विभिन्न विषयों जैसे फसल बीमा, फसल कटाई, फसलों में लगने वाले रोग, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, टमाटर की खेती, मृदा नमूना कैसे लें, टमाटर में लगने वाले रोग, प्रति हेक्टेयर खेती की लागत, ड्रिप इरीगेशन सिस्टम इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण उपरांत कलेक्टर शिवपुरी के निर्देशानुसार समस्त प्रशिक्षणार्थियों की एक परीक्षा का आयोजन किया गया जिसका परिणाम मूल्यांकन उपरांत दो या तीन दिवस के अंदर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जावेगा।

प्रशिक्षण में डॉ. पुनीत कमार वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी, उम्मेद सिंह तोमर उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह वैज्ञानिक, डॉ. ए. एल. बसेड़िया वैज्ञानिक, डॉ. नीरज कुमार कुशवाहा वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी कृषि विज्ञान केन्द्र शिवपुरी ने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही उनकी जिज्ञासाओं का समाधान किया। इस कार्यक्रम में आरती बसंल स्टेनो का भी सहयोग रहा। इस प्रशिक्षण में 59 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया।

मल्टीनेशनल कंपनी की जॉब छोड़ इंजीनियर बना किसान

7 एकड़ में 30 वैरायटी के देसी-विदेशी आम के पेड़ तैयार किए, इनकम 12 लाख रुपए

बैतूल। जागत गांव हमार

बैतूल का युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर मल्टीनेशनल कंपनी में लाखों रुपए का पैकेज छोड़कर खेती किसानी करने लगा। ये हैं बैतूल जिले के विजय पवार। जागत गांव हमार अपने इस अंक में पाठकों को विजय की कहानी बता रहा है। पवार मुलताई के ग्राम दुनावा के रहने वाले हैं। उन्होंने सात एकड़ में देसी-विदेशी आम के पेड़ लगाए हैं। इस बगीचे से हर साल करीब 10 से 12 लाख रुपए का आमदनी हो रही है। पवार का कहना है कि परंपरागत खेती से हटकर अगर इस तरह की खेती की जाए, तो नुकसान की आशंका कम रहती है।

विजय पवार से जानते हैं कि कैसे हो रही लाखों में आय

मैं 2013 तक पुणे में मल्टीनेशनल कंपनी में बतौर सॉफ्टवेयर डेवलपर काम कर रहा था। यहां सालाना पैकेज सात लाख रुपए था। काम भी ठीक चल रहा था। फिर एक दिन घर से फोन आया कि पिताजी का तबीयत खराब हो गई। जल्दी आ जाओ। मैं अगले दिन ही गांव आ गया। अस्पताल में इलाज के बाद पापा की तबीयत में सुधार होने लगा। मैं भी पिता का देखभाल कर रहा था। इस दौरान देखा कि पारंपरिक खेती चल रही है। इसमें उतनी कमाई नहीं होती। मौसम की भी मार पड़ती रहती है। सोचने लगा कि कैसे यहां रहकर पिता के सेवा के साथ ही कुछ नया किया जाए। फिर दिमाग में आधुनिक तरीके से खेती-किसानी करने का आइडिया आया। इसके बाद करीब 6 महीने तक आम की फार्मिंग, इसके बाजार और मार्केटिंग पर रिसर्च किया। कई कृषि विशेषज्ञों, किसानों से राय ली। इसके बाद आम की खेती शुरू की। मैंने 7 एकड़ में 30 वैरायटी के आम के करीब 1200 पौधे लगाए। इसमें हापुस, लंगड़ा, चौसा, दशहरी, केसर, तोता परी के पेड़ ज्यादा हैं। विदेशी वैरायटी में सन ऑफ एग, किंग ऑफ मैंगो भी है। पहले पेड़ों के बीच-बीच में बची जगह में खेती करते थे। अब पेड़ बड़े हो गए हैं, तो ट्रैक्टर घुमाने में दिक्क त होती है, इसलिए नहीं कर रहे हैं। ये बगीचा 8 साल

में तैयार किया है। पुणे से लौटने से पहले पिता भी सभी किसानों के तरह ही परंपरागत तरीके से ही खेती करते थे। 17 एकड़ खेत से सालाना दो से ढाई लाख रुपए आमदनी हो रही थी। इसमें साल दर साल लागत भी बढ़ती जा रही थी। पहले खुद ही आम बेचता था। इससे दूसरे कामों पर ध्यान नहीं दे पा रहा था, इसलिए अब बगीचे को ठेके पर देना शुरू दिया है। हर साल ऑक्शन होता है, जो ऊंचे दामों पर ठेके पर लेता है, उसे आम बेचने का अधिकार होता है। साथ ही, मेंटेनेंस का जिम्मा भी ठेकेदार का होता है। इससे सीधा 10 से 12 लाख का मुनाफा हो जाता है। इतनी कमाई में अपने घर-गांव से दूर रहकर भी नहीं कर पा रहा था। यहां खेती-किसानी से मुझे एक अलग प्रकार सुकून भी मिलता है।

अब जानते हैं, आप कैसे कर सकते हैं आम की फार्मिंग

खेत में सबसे पहले 10 फीट की बराबर दूरी पर गड्ढे खोद लें। इसमें कुछ गोबर खाद मिलाकर मिट्टी डाल लें। कुछ दिन तक गड्ढों को ऐसे ही छोड़ दें। 8 से 10 दिन बाद इनमें पौधे लगाते हैं। जून-जुलाई से सितंबर तक प्लांटेशन कर देना चाहिए। इसके लिए पानी पर्याप्त होना चाहिए। अलग-अलग वैरायटी में एक पौधे तैयार होने में तीन से सात साल लगता है।

मानसून शुरू होने से पहले पौधों में दें खाद

आम की फसल का उत्पादन तो वैसे सभी तरह की भूमि में किया जा सकता है, लेकिन अच्छी जल धारण क्षमता वाली गहरी, बलुई दोमट सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भूमि का पीएच मान 5.5-7.5 तक इसकी खेती के लिए उपयुक्त माना जाता है। अल्फांसो के लिए खास तरह की जमीन और जलवायु की जरूरत होती है। एक साल पुराने पेड़ को मानसून शुरू होने से पहले कम्पोस्ट खाद, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाश देना चाहिए।

पौधों की देख-रेख भी जरूरी

अच्छे उत्पादन के लिए पौधों की देख भाल करना जरूरी है। शुरुआती तीन चार साल तक तो ध्यान देने की जरूरत है। सर्दी में पाले से बचाने के लिए और गर्मी में लू से बचाने के लिए सिंचाई का प्रबंधन करना चाहिए। जमीन से 80 सेमी तक की शाखाओं को निकाल देना चाहिए।

पौधों को कीट और रोग से ऐसे बचाते हैं

कुछ कीट फलों के पत्तों, पंखुड़ियों और डंठल से रस को अवशोषित करते हैं। इससे पत्तियां मुरझा जाती हैं। फूल झड़ जाते हैं। साथ ही, छोटे-छोटे फल भी झड़ जाते हैं। शाखाओं को इस तरह से पतला किया जाना चाहिए कि कीट नियंत्रण के लिए बगीचे में पर्याप्त धूप हो। समय-समय पर बगीचे का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए। डिमेथोएट 30 ईसी या मैनिट्रोथियन कीटनाशकों का छिड़काव किया जाना चाहिए।

इनके रेस्टोरेंट में बनी दूध की मिठाइयां भी फेमस

आम की खेती के साथ ही विजय पवार रेस्टोरेंट भी चलाते हैं, जहां दूध से बनी मिठाइयां फेमस हैं। इसके लिए दूर-दूर से लोग आते हैं। यहां कि मिठाई की खासियत है कि इसमें शक्कर की मात्रा कम होती है। ये ताजे दूध को पकाकर बनाई जाती है। अच्छी क्वालिटी होने की वजह से लोग मिठाइयां पैक करवाकर ले जाते हैं।

नलजल योजना के संचालन का कार्य महिला स्वसहायता समूहों को सौंपा जाएः मुख्यमंत्री

भोपाल मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत नलजल योजना के संचालन का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा जाए। मिशन के अंतर्गत बनी संरचनाओं के दीर्घकालीन संचालन के लिए ग्राम स्तर पर भू-जल भण्डारण की क्षमता बढ़ाने की गतिविधियां चलाना आवश्यक है, इसके लिए ग्राम स्तर पर जनजागृति अभियान चलाकर जनभागीदारी को प्रोत्साहित किया जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंत्रालय में जल जीवन मिशन की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मलय श्रीवातव, डॉ. राजेश राजौरा, जे एन कंसोटिया, प्रमुख सचिव मनीष सिंह तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में 63 प्रतिशत से अधिक घरों को नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रदेश के समस्त ग्रामीण परिवारों को नल से जल उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य तेजी से जारी है। जिन क्षेत्रों में कठिनाई आ रही है वहां कठिनाईयों और विसंगतियों को व्यावहारिक रूप से दूर करते हुए मध्यप्रदेश को हर घर नल से जल उपलब्ध कराने में देश में मॉडल राज्य के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हर स्तर पर कार्य हो। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जल जीवन मिशन की गतिविधियों को त्वरित और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने वाले विधानसभा क्षेत्रों, जिलों, जनपद, ग्राम पंचायत आदि को पुरस्कृत किया जाए।

70 लाख 72 हजार 875 ग्रामीण परिवारों को उपलब्ध कराया जा रहा है नल से जल

मुख्यमंत्री ने कहा कि गावों में आम जन को पीने का पानी सरलता से उपलब्ध कराने के लिए प्याऊ लगाने, पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था करने और छायादार स्थान बनाने के लिए सामाजिक पहल को प्रोत्साहित किया जाए। पानी के मितव्ययी उपयोग और पाइप आदि के संधारण में सभी ग्रामवासी सतर्कता और जागरूकता के साथ अपना योगदान दें। बैठक में बताया गया कि प्रदेश के कुल एक करोड़ 11 लाख 82 हजार 86 ग्रामीण परिवारों में से 70 लाख 72 हजार 875 परिवारों को जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल उपलब्ध कराया जा रहा है।

एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के तहत पौधरोपण

रीवा। कृषि विज्ञान केन्द्र रीवा म प्र में एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अन्तर्गत वृक्षारोपण केंद्र के प्रभारी एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. राजेश सिंह के साथ कृषक एवं केंद्र के वैज्ञानिकों के सहयोग से किया गया। यह कार्यक्रम पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मिले दिशा निर्देशों के अनुसार किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत प्रधानमंत्री द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पीपल का पेड़ लगा कर किया गया है। इस कार्यक्रम में किसानों को जागरूक किया गया और बताया गया कि आगामी वर्षा काल में विभिन्न प्रकार के पेड़ लगाए जाएंगे। इस अवसर पर केंद्र के वैज्ञानिक डॉ.केसी सिंह, डॉ. बीके तिवारी, डॉ. अखिलेश कुमार, डॉ. स्मिता सिंह, डॉ. केयेस बघेल, संदीप शर्मा, मंजू शुक्ला एवं प्रगतिशील कृषक उपस्थित रहे।

प्रवाह क्षेत्र अविरल हो, नर्मदा किनारे के ग्रामीण भाइयों को मिले परिवहन सुविधा मुख्यमंत्री डॉ. यादव

केंद्र सरकार से जल संरक्षण और सिंचाई योजनाओं के लिए मिलेगा भरपूर सहयोग, नर्मदा जी से काफी कुछ लिया है नर्मदा जी को हम कुछ दें भी

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में नर्मदा घाटी विकास विभाग के अंतर्गत नर्मदा नियंत्रण मंडल की गतिविधियों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नर्मदा जी के प्रमुख घाटों पर जल प्रवाह सुनिश्चित किया जाए। प्रदेश में सिंचाई के साधनों के विस्तार का कार्य निरंतर हो।

केंद्र सरकार से ऐसे कार्यों के लिए पर्याप्त धन राशि भी प्राप्त होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, राज्य मंत्री द्वय वी सोमन्ना और राजभूषण चौधरी से जल संरक्षण कार्यों के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। मध्यप्रदेश के हितों के लिए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग प्राप्त होगा। प्रदेश के दो बड़े नदी जोड़ो अभियान केन-बेतवा लिंक परियोजना और पार्वती काली सिंध परियोजना के क्रियान्वयन के विषयों पर भी निर्णायक बातचीत हुई है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि किसानों को सस्ते दाम पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए जल विद्युत के नए स्रोत विकसित किए जाएं। वैकल्पिक ऊर्जा के स्रोतों का उपयोग भी किया जाए।

किसानों को मिले सस्ती बिजली

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि हमने नर्मदा से काफी कुछ लिया है। हम नर्मदा को कुछ देने का भी सोचें। सभी सार्वजनिक घाट स्वच्छ और सुंदर हों इसके लिए प्रशासनिक अमले और आमजन को सजग रहना है। जन श्रद्धा के विभिन्न स्थानों को विकसित किया जाए। आमजन की उपयोगिता के अनुरूप घाटों के अलावा नदी के पास स्थित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों को भी सुविधायुक्त बनाया जाए। नर्मदा परि मा करने वाले यात्रियों के लिए शेड आदि बनाए जाएं। जन अभियान परिषद और अन्य स्वैच्छिक संगठन परि मावासियों के लिए अन्य सुविधाओं के विकास के लिए प्रयास करें। वॉटर स्पोर्ट्स गतिविधियों पर भी ध्यान दिया जाए। पर्यटन विकास की दृष्टि से योजनाएं लागू करने को भी प्राथमिकता दें। इसी तरह ग्रामवासियों की सहूलियत को देखते हुए नर्मदा जी में छोटे माल वाहक जहाज के संचालन और मत्स्य पालन की संभावना पर भी कार्य किया जाए। नर्मदा घाटी से संबंधित जैव विविधता का शोध भी किया जाए। मोती की खेती के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इन सभी कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग हो। आवश्यकता अनुसार जल पुलिस की व्यवस्था भी होना चाहिए जो प्रमुख घाटों और नदी के किनारे स्थित स्थानीय निवासियों के हित में कार्य करे। ओंकारेश्वर की तरह अन्य स्थानों पर भी नवकरणीय ऊर्जा का उपयोग किया जा सकता है। सोलर फ्लोटिंग प्लांट लगाने के स्थान चिन्हित करने की कार्रवाई करें। इस संबंध में आगामी ग्लोबल समिट में इस क्षेत्र में इच्छुक निवेशकों को आमंत्रित किया जा सकता है।

तालाबों में पानी के अधिकतम उपयोग के प्रयास किए जाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि नर्मदा जी की डाउनस्ट्रीम स्थित तालाबों में पानी के अधिकतम उपयोग के प्रयास किए जाएं। यशवंत सागर सहित अन्य जलाशयों में जल उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए, जिससे ग्रीष्मकाल में जल राशि के माध्यम से संकट की स्थिति को टालने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने पम्प स्टोरेज प्रणाली से सस्ती बिजली का प्रयोग बढ़ाने, गांव के लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी के उद्देश्य से वाटर एम्बुलेंस संचालन के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। बैठक में स्वीकृत परियोजनाओं के निकट भविष्य में लोकार्पण पर भी चर्चा हुई। नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेजेंटेशन के माध्यम से ि यान्वित योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी गई। बैठक में बड़ादेव संयुक्त माइक्रो सिंचाई परियोजना, मां रेवा उद्वहन सिंचाई परियोजना, सोंडवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, निवाली उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, महेश्वर जानापाव उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, सेंधवा उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना, धार उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना सहित अन्य परियोजनाओं के संबंध में चर्चा हुई। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह बैठक से वर्चुअली जुड़े।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने विश्वविद्यालय को दिया प्रोजेक्ट, पैंतालीस लाख रुपए भी दिए

कम पानी में बाजरे की नई किस्म पर शोध हुआ शुरू

ग्वालियर। जागत गांव हमार

मोटा अनाज यानि श्री अन्न स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद है। यही वजह है कि देश ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कोदो, कंगनी और समा को बड़े चाव खा रहे हैं। यही वजह है कि मोटे अनाज की डिमांड बढ़ गई है, लेकिन मोटे अनाज का उत्पादन कम ही हो रहा है। इसे लेकर ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाजरा की (ऐसी किस्म जो ज्यादा गर्मी और कम पानी में तैयार हो सके) को लेकर लिए राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि ग्वालियर को प्रोजेक्ट दिया है और इसके लिए 45 लाख रुपए दिए हैं। विवि को यह प्रोजेक्ट 2026-27 तक पूरा करना है। विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला के निदेज़्शन में वैज्ञानिक डॉ. सुषमा तिवारी ने इस विषय पर काम करना भी शुरू कर दिया है।

बीज डालकर भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा

वैज्ञानिक डॉ. सुषमा तिवारी ने बताया कि कम पानी और ज्यादा तापमान में बाजरे की फसल हो सके, इसके लिए खेतों में बाजरे के बीजों को अलग-अलग क्यारियों में बोया जाएगा। एक क्यारी में पानी, खाद दिया जाएगा और दूसरी क्यारी को भगवान भरोसे छोड़ दिया जाएगा। इसके बाद देखा जाएगा कि दोनों क्यारियों में क्रॉप कितने दिन में निकलती है। इसके साथ ही यह देखा जाएगा कि कितने दिन के अंदर फसल तैयार हो रही है। उनका कहना है कि एक साल में दो बार ऐसा प्रयोग किया जाएगा।

- बाजरे की फसल कम पानी और ज्यादा तापमान में तैयार हो सके, इसके लिए आईसीएआर से प्रोजेक्ट मिला है। विवि ने इसके ऊपर शोध शुरू कर दिया है।

प्रो. अरविंद कुमार शुक्ला,
कुलपति कृषि विवि ग्वालियर

जेएनकेविवि ने किसानों को शकर के विकल्प की खेती के लिए किया तैयार

जबलपुर की स्टीविया की विदेशों में मांग

रूस से आई 1 कंटेनर की डिमांड

जबलपुर। डायबिटीज और बीपी की समस्या से ग्रस्त मरीजों के लिए वरदान बन रही स्टीविया की पत्तियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। शकर से 300 गुना तक अधिक मिठास वाली जबलपुर की इन पत्तियों की मांग प्रदेश में भोपाल, इंदौर और छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र के साथ विदेशों में भी बढ़ गई है। स्थानीय किसानों के एक समूह को मॉस्को (रूस) की एक कंपनी की ओर से 3 कटेंनर (1 कटेंनर में 20 टन) यानि 60 टन की डिमांड आई है। जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि के हर्बल प्लांट में इस पत्ती की मांग पिछले एक साल में 25 किलो से बढ़कर एक क्विंटल तक पहुंच गई है। यह डिमांड स्थानीय लोगों और पड़ोसी जिलों की है।

- ऑर्गेनिक फार्मिंग से तैयार एक क्विंटल पत्तियों की कीमत बाजार में करीब 20-25 हजार रुपए है।
- बिना ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए गए पौधों की पत्तियों के एक क्विंटल की कीमत 8-10 हजार रुपए।
- एक किलो पत्ती के पावडर की कीमत करीब 400-450 रुपए।
- एक किलो पत्ती 20 किलो शकर के बराबर मिठास देती है।
- विशेषज्ञों के मुताबिक स्टीविया की पत्तियों में कैलोरी की मात्रा शून्य होती है।

- हमारे पास मास्को की एक कंपनी की ओर से 60 टन की डिमांड आई है, जिसे हमें जनवरी तक पूरा करना है। इसके लिए 25 एकड़ से अधिक में खेती की गई है। डिमांड को देखते हुए किसानों का समूह बना कर खेती की जा रही है। रकबा भी बढ़ा दिया गया है।

- अंबिका पटेल, किसान

- स्टीविया की पत्तियों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए अब एक एकड़ में करीब 35 हजार से अधिक पौधों की खेती की गई है।

-डॉ. ज्ञानेंद्र तिवारी,
प्रोफेसर, जेएनकेे विवि

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादक: अजय कुमार द्विवेदी, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेल:- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)